रेप मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई आसाराम की पेशी

गांधीनगर, 7 फरवरी (ए)। स्वयंभू संत आसाराम के खिलाफ सूरत की एक महिला द्वारा दर्ज कराये गए बलात्कार के एक मामले में वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश हुआ। वह अभी राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राशीदा वोरा की अदालत में आज पीड़ित से पूछताछ शुरू हुई। आसाराम के वकील बी एम गुप्ता ने बताया कि उससे पूछताछ कल भी जारी रहेगी। अदालत ने अपनी पिछली सुनवाई के समय आसाराम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होने का आदेश दिया था।

ओमान में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने का इंतजार : मोदी

नयी दिल्ली, 7 फरवरी (ए)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उन्हें ओमान की अपनी यात्रा के दौरान 11 फरवरी को भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने का इंतजार है। मोदी 11 और 12 फरवरी को इस खाड़ी देश में रहेंगे। उन्होंने कहा, 'मुझे 11 फरवरी को मस्कट में एक बड़े सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करने का इंतजार है। भारतीय समुदाय के लोगों से मिलना प्रसन्नता की बात होगी। कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप पर साझा करें। मैं उनमें से कुछ का अपने संबोधन में उल्लेख करूंगा।' मोदी अपनी यात्रा के दौरान मस्कट में 200 वर्ष पुराने एक शिव मंदिर और सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद भी जाएंगे।

जम्मू में दुष्कर्म आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत

जम्मू, 7 फरवरी (ए)। दुष्कर्म मामले के एक आरोपी की आज यहां पुलिस हिरासत में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गयी। सूत्रों के मुताबिक जम्मू के जानीपुर निवासी सुभाष चंद्र उर्फ काका (50) को एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के आरोप में गत दो फरवरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसकी हिरासत में रहते हुए मौत हो गयी। सूत्रों के मुताबिक उसने कथित रुप से आत्महत्या कर ली जबकि पुलिस का दावा है कि दिल का दौरा पड़ने से उसका निधन हो गया। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

मेघालय चुनाव : सीएम मुकुल संगमा ने दाखिल किया नामांकन

शिलांग, 7 फरवरी (ए)। मेघालय के मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र अमपाटी से नामांकन दाखिल किया, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनपीपी की नेता अगाथा के संगमा ने दक्षिण तूरा सीट से पर्चा भरा। कल मेघालय विधानसभा चुनाव के वास्ते नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार वर्ष 2010 से इस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री मुकुल संगमा दो सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अमपाटी सीट से आज नामांकन दाखिल किया जबकि वह कल पूर्वी गारो पर्वतीय जिले में सोंगसाट निर्वाचन क्षेत्र से पर्चा भरेंगे। उन्होंने बताया कि मुकुल संगमा दक्षिण पश्चिम गारो पर्वतीय जिले में अमपाटी सीट से पांचवीं बार चुनाव जीतने का जतन कर रहे हैं। अगाथा संगमा और उनके भाई पूर्व सांसद थॉमस ए संगमा ने भी आज नामांकन दाखिल किया।

वित्तमंत्री ने बजट में अपना दिमाग नहीं लगाया : सिन्हा

कोलकाता, 7 फरवरी (ए)। भाजपा के असंतुष्ट नेता व पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 2018-19 के आम बजट की आलोचना करते हुए आज कहा कि इसे बनाने में कोई दिमाग नहीं लगाया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट पिछले सप्ताह लोकसभा में पेश किया था। सिन्हा ने कहा कि बजट में वैश्विक व घरेलू संदर्भों को ध्यान में नहीं रखा गया। उन्होंने यहां कलकत्ता चैंबर आफ कामर्स की एक संगोष्ठी में कहा, 'ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में अपना दिमाग नहीं लगाया। अगर ऐसा है तो उन्होंने बजट तैयार करते समय भी अपना दिमाग नहीं लगाया होगा।' सिन्हा ने कहा कि बजट में विशेषकर स्वास्थ्य क्षेत्र सहित अनेक योजनाओं की घोषणा की गई है जिन पर पर्याप्त सोच विचार नहीं किया गया।

बिना रोडमैप के चल रहा है कश्मीर की आजादी का आन्दोलन : आसिया अन्द्राबी

श्रीनगर, 7 फरवरी (ए)। कट्टरवादी अलगाववादी नेता आसिया अन्द्राबी ने अलगाववादियों द्वारा बार-बार दिये जा रहे हड़ताल के आह्वान को आजादी आन्दोलन के नाकाफी करार दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आजादी का आन्दोलन बिना रोडमैप के चल रहा है। बार-बार हड़ताल का आह्वान कर दिया जाता है पर यह पर्याप्त नहीं है, यह हमे कहीं नहीं लेकर जाएगा। मुस्लिम दीनी महज के चीफ डा कासिम के जेल में 25 वर्ष पूरे होने को लेकर आयोजित एक सेमीनार में आसिया ने लोगों को संबोधित किया।

ईरान ने अमेरिकी नागरिक को वापस जेल भेजा : अमेरिकी अधिकारी

बोगोटा 7 फरवरी (ए)। अमेरिका ने आज शिकायत की कि ईरानी अधिकारियों ने 81 वर्षीय अमेरिकी नागरिक को इलाज के बाद वापस जेल भेज दिया है। अमेरिका के विदेश उपमंत्री स्टीव गोल्डस्टीन ने संवाददाताओं को बताया कि बैंकेर नमाजी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और उन्होंने यूनीसेफ के पूर्व अधिकारी को मानवीय आधार पर तुरंत रिहा करने की अपील की। गोल्डस्टीन ने कहा, 'हम इस बात से बहुत निराश हैं कि ईरानी सरकार ने नमाजी को फिर से जेल में डाल दिया है। हम उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर चिंतित हैं और उन्हें लगातार चिकित्सीय देखरेख की तुरंत जरुरत है। अमेरिका-ईरान की दोहरी नागरिकता रखने वाले नमाजी को ईरानी अधिकारियों ने रविवार को मानवीय आधार पर जेल से छुट्टी दी थी। सितंबर में उनकी दिल की आपात सर्जरी हुई थी। नमाजी को जासूसी और अमेरिकी सरकार के साथ मिलीभगत'' के दोष में अक्तूबर में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि अमेरिकी सरकार और नमाजी का परिवार इन आरोपों को खारिज करता है।

राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी सैनिकों का करते हैं समर्थन : प्रेस सचिव

वॉशिंगटन 7 फरवरी (ए)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के शक्ति प्रदर्शन और कमांडर-इन-चीफ के तौर पर अपनी भूमिका को रेखांकित करने के लिए सैन्य परेड आयोजित करने को कहा है। व्हाइट हाउस ने आज बताया कि राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले से परेड के आयोजन का विचार रखने वाले ट्रंप ने अधिकारियों से इस संबंध में अनुरोध किया है। अधिकारी परेड के लिए सही तारीख की खोज में हैं।

कांग्रेस को भरोसा, 2019 में नहीं होगी मोदी की बतौर पीएम वापसी

नई दिल्ली 7 फरवरी (ए)। राजस्थान उपचुनाव के नतीजों ने कांग्रेस में एक बार फिर से जान फूंक दी है। पार्टी का मानना है कि कुछ राज्यों में बैकफुट पर दिख रही कांग्रेस अब पहले से बेहतर हालत में है। कांग्रेस पार्टी को पूरा भरोसा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पार्टी मजबूत हुई है और हरियाणा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का प्रभाव बढ़ा है। इसी आत्मविश्वास और छिटपुट सकारात्मक नतीजों के कारण पार्टी के कुछ नेताओं को लग रहा है कि 2019 में मोदी फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि कांग्रेस 60 ऐसी सीटों का चयन कर सकती है जहां पीएम मोदी + को पिछले चुनाव में दिक्कत हुई थी। सूत्र ने यह भी कहा कि दुबारा पीएम बनने के लिए पीएम मोदी के सामने एक चुनौती गठबंधन वाली पार्टियों की तरफ से भी आ रही है। पीएम गठबंधन पार्टियों के साथ कुशलता से काम करने में नाकाम रहे हैं। कांग्रेस की इस पर नजर है। एनडीए सरकार में कुछ क्षेत्रीय पार्टियां खुद को सहज नहीं मान

रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का मानना है कि 2019 लोकसभा चुनावों को लेकर उनका अनुमान है कि नरेंद्र मोदी फिर से पीएम नहीं चुने जा सकेंगे। नेता ने बताया, ऐसा लग रहा है कि 2019 में या तो कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी अगर सत्ता में वापस भी आई तो पीएम नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। मोदी की कार्यशैली गठबंधन को बनाकर रखने की नहीं है। शिवसेना, टीडीपी + और अकाली दलों की तरफ से आ रही टकराव की खबरें इस बात को पुष्ट करती हैं। अनौपचारिक बातचीत में कांग्रेस नेता ने यह भी कहा, एक संभावना है कि बीजेपी और पीएम मोदी अगर फिर से चुनाव जीतने में सफल भी रहे तो बीजेपी की 282 सीटों की तुलना में यह जीत 220 के आसपास ही रहेगी। गठबंधन पार्टियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वश्रेष्ठ विकल्प नहीं है। उनकी तुलना में राजनाथ सिंह बेहतर तरीके से गठबंधन धर्म निभा सकते हैं। कांग्रेस का आत्मविश्वास राजस्थान उपचुनाव में 2 लोकसभा सीटें जीतने के बाद बढ़ा है। पार्टी का राज्य से एक भी नेता 2014 में लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाया। गुजरात चुनावों में प्रदर्शन अच्छा होने और राजस्थान उपचुनावों में मिली जीत के कारण पार्टी और खुद राहुल गांधी का भरोसा बढ़ा है। दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर कुछ राज्यों में बीजेपी की पकड़ कमजोर होने की खबरों के बीच गठबंधन में नाराजगी की बातें भी कांग्रेस का मनोबल बढ़ा रही है।

पाक आतंकी को छुड़ा ले जाना देश के लिए अच्छा नहीं : आजाद

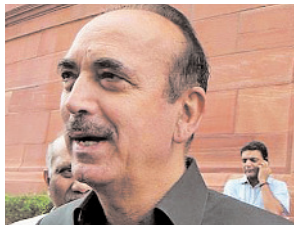

नई दिल्ली 7 फरवरी (ए)। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कल एक पाक आतंकवादी को कश्मीर के अस्पताल से छुड़ा लेने की घटना को गंभीर मुद्दा बताते हुए इसके लिए राज्यसरकार को दोषी ठहराया और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कारवाई करने की मांग की है। आजाद ने आज नियम 267 के तहत इस मुद्दे पर कार्यस्थगन का नोटिस दिया था और इस पर विस्तृत चर्चा की मांग की लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसे मंजूर नहीं किया और उन्हें शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी। कांग्रेस नेता ने ऐसे अस्पताल में चेक उप के लिए ले जाया गया जहां ओ पी डी में हजारों लोगों की भीड़ रहती है और जो सबसे पुराना अस्पताल है। उस अस्पताल में अर्ध सैनिक बालों को तैनात किया जाना चाहिए था लेकिन यह राज्य सरकार की कमी है।

मनोज तिवारी ने राजनाथ से कहा वाई श्रेणी की सुरक्षा पर्याप्त नहीं

नयी दिल्ली 7 फरवरी (ए)। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने गृह मंत्रालय से इस आधार पर अपनी सुरक्षा बढ़ा कर जेड श्रेणी का करने का अनुरोध किया है कि वर्तमान सुरक्षा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उन पर कथित हमले के दौरान और राज्यों के उनके प्रचार के मद्देनजर अपर्याप्त साबित हुई है। तिवारी सहित दिल्ली भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाया है कि शहर में सीलिंग अभियान से प्रभावित व्यापारियों को राहत मुहैया कराने का रास्ता निकालने के लिए जब वे लोग गत 30 जनवरी को केजरीवाल के आधिकारिक आवास गए थे तब वहां आप विधायकों और ''असामाजिक तत्वों'' ने ''दुर्व्यवहार और हमला'' किया था। तिवारी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखे अपने पत्र में कहा कि उनके पास वाई श्रेणी की सुरक्षा है लेकिन हाल की घटनाओं के मद्देनजर वह अपर्याप्त साबित हुई है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, ''दो घटनाएं...पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य में प्रचार के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने से इनकार करना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमला...यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं हैं।'' उन्होंने पार्टी के ''प्रचार और विस्तार'' के लिए अन्य राज्यों के अपने दौरों का उल्लेख किया और सिंह से जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध किया।

सस्पेंड करने की खबर से तमतमाए एएसआई ने ओपी अध्यक्ष को मारी गोली

कटिहार 7 फरवरी (ए)। पुलिस को कानून का रखवाला कहा जाता है, लेकिन अगर वही पुलिस कानून की धज्जियां उड़ाने लग जाए तो फिर आम जन से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। ताजा मामला बिहार के कटिहार का है। जहां निलंबन की कार्रवाई से गुस्साए सुधानी ओपी के एएसआइ जाकिर हुसैन ने ओपी अध्यक्ष राकेश रमण को गोली मार दी। वहीं इस घटना से पूरे पुलिस प्रशासन में तहलका मचा हुआ है। एएसआइ की अनुशासनहीनता को लेकर ओपी अध्यक्ष ने एक रिपोर्ट एसपी को दी थी। इस मामले को सही पाते हुए एसपी ने सोमवार की रात ही उसे निलंबित कर दिया था।

इसकी भनक लगते ही मंगलवार को तमतमाए निलंबित एएसआइ ओपी परिसर स्थित उनके आवास पर पहुंच गए। जहां निलंबन की बात को लेकर ओपी अध्यक्ष से उसकी कहा सुनी हुई। इसी बीच एएसआई ने सर्विस पिस्टल निकाल ओपी

अध्यक्ष पर गोली चला दी। एक गोली ओपी अध्यक्ष के बाएं हाथ में लगी, जबकि दूसरी गोली उसके दाएं हाथ की अंगुली को छूती हुई निकल गई। हमले वे बाल-बाल बच गए। जब तक परिसर में मौजूद अन्य पुलिस कर्मी कुछ समझ पाते आरोपित एएसआइ सर्विस पिस्टल के साथ वहां से फरार हो गया।

ओपी अध्यक्ष को मेडिकल कालेज में किया रेफर : वहीं मौके पर मौजूदा लोगों ने आनन-फानन में जख्मी अवस्था में ओपी अध्यक्ष को बारसोई रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में उसे कटिहार मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया।

गिरफ्तारी के दिए निर्देश : सूचना मिलते ही बारसोई एसडीपीओ पंकज कुमार सहित बारसोई एवं बलरामपुर पुलिस मौके पर पहुंची। फरार एएसआइ की गिरफ्तारी का निर्देश देते हुए विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बाद में एसडीओ फिरोज अख्तर ने भी बारसोई अनुमंडल अस्पताल पहुंच उनका हाल लिया।

विजय माल्या को दिये कर्ज का रिकॉर्ड ही नहीं है वित्त मंत्रालय के पास

नई दिल्ली 7 फरवरी (ए)। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सूचना आयोग से कहा है कि उसके पास उद्योगपति विजय माल्या को दिये गए कर्ज के बारे में सूचना नहीं है। इस पर सूचना आयोग ने कहा कि मंत्रालय का जवाब 'अस्पष्ट और कानून के अनुसार टिकने योग्य' नहीं है। मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर ने राजीव कुमार खरे के आवेदन पर सुनवाई करते हुए वित्त मंत्रालय के अधिकारी से कहा कि आवेदक द्वारा दिये गए आवेदन को उचित लोक प्राधिकारी को स्थानांतरित किया जाए। वित्त मंत्रालय के अधिकारी भले ही दावा करें कि उनके पास माल्या को विभिन्न बैंकों द्वारा दिये गए कर्ज या इन कर्ज के बदले में

माल्या द्वारा दी गई गारंटी के बारे में सूचना नहीं है, लेकिन मंत्रालय ने अतीत में इस संबंध में सवालों का संसद में जवाब दिया था। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने 17 मार्च 2017 को माल्या पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि जिस व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया गया (माल्या को) उसे 2004 में कर्ज दिया गया और फरवरी 2008 में उसकी समीक्षा की गई।

उन्होंने कहा था, ''साल 2009 में 8040 करोड़ रुपये के कर्ज को एनपीए घोषित किया गया और 2010 में एनपीए को रिस्ट्रक्चर किया गया।'' गंगवार ने 21 मार्च को राज्यसभा में कहा था, ''पीएसबी ने जैसा रिपोर्ट किया, कर्ज अदायगी में चूक करने वाले कर्जदार विजय माल्या की जब्त की गई संपत्तियों की मेगा ऑनलाइन नीलामी के जरिये बिक्री करके 155 करोड़ रुपये की रकम वसूल की गई है।''

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 17 नवंबर 2016 को नोटबंदी पर उच्च सदन में चर्चा के दौरान माल्या के कर्ज मुद्दे को 'भयानक विरासत' बताया था, जो राजग सरकार को पूर्ववर्ती संप्रग सरकार से विरासत में मिली थी। हालांकि, खरे को वित्त मंत्रालय से अपने आरटीआई आवेदन का जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने सीआईसी का दरवाजा खटखटाया था।

गोवा के खान मालिकों को सुप्रीम कोर्ट का झटका

नई दिल्ली 7 फरवरी (ए)। उच्चतम न्यायालय ने गोवा के खान मालिकों को आज तगड़ा झटका देते हुए राज्य में खनन के पट्टों का नवीनीकरण रद्द कर दिया। न्यायाधीश मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने आज अपने आदेश में कहा कि गोवा में खनन गतिविधियां केवल इस वर्ष 16 मार्च तक ही जारी रह सकेंगी। गोवा में खनन के 88 पट्टों के ताजा नवीनीकरण के फैसले को अधिकता प्रशांत भूषण ने चुनौती दी थी। इन पट्टों की नीलामी राज्य सरकार ने की थी। शीर्ष न्यायालय ने खनन कर रहीं कंपनियों को निर्देश दिया है कि वह अपना परिचालन 16 मार्च तक समेट लें। खनन के पट्टों का नवीनीकरण रद्द करते हुए शीर्ष अदालत ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया है कि गोवा में खनन कंपनियों को पट्टे देने के लिए फिर से नीलामी की प्रक्रिया शुरु की जाये। इससे पहले अक्टूबर 2012 में उच्चतम न्यायालय ने गोवा में लौह अयस्क के खनन और इसकी आवाजाही को निलंबित कर दिया था। यह आदेश शीर्ष न्यायालय ने न्यायाधीश एम बी शाह कमीशन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दिया था। रिपोर्ट में कहा गया था बडी संख्या में खनन कंपनियां लाखों टन लौह अयस्क का गैरकानूनी ढंग से खनन कर रही हैं।

ब्रिटेन अदालत की असांजे को 2 टूक, इक्वेडोर से निकलने की उम्मीद कम

लंदन, 7 फरवरी (ए)। सनसनीखेज खुलासे करने के लिए मशहूर वेबसाइट विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के खिलाफ2012 में मशहूर जारी गिरफ्तारी का वारंट अभी भी बरकरार है। ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर की मैजिस्ट्रेट अदालत की मुख्य मैजिस्ट्रेट एम्मा अर्बुथनॉट ने तर्क दिया कि वह असांजे के वकीलों के 'इस बात से सहमत नहीं है कि वारंट वापस ले लिया जाना चाहिए। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के वकीलों ने एक ब्रिटिश अदालत का रुख कर अपने मुवक्किल के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारेंट वापस लेने की गुहार लगाई थी।

अगर यह गिरफ्तारी वारंट वापस ले लिया जाता तो असांजे करीब 5 साल बाद इक्वेडोर के दूतावास से खुलकर बाहर निकल सकते थे जो अब संभव नहीं दिख रहा है।असांजे के वकीलों ने कहा अदालत में अपनी दलील में कहा था कि इस वारंट का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि कथित यौन अपराधों के

मामले में पूछताछ के लिए अब उनके मुवक्किल की जरूरत नहीं है। स्वीडन के वकीलों ने पिछले साल मुकदमा बंद करते हुए कहा था कि असांजे को निकट भविष्य में स्वीडन लाए जाने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अभी अगर असांजे लंदन स्थित इक्वेडोर के दूतावास से बाहर निकलते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। वह 2012 से ही इक्वेडोर के दूतावास में रह रहे हैं. उन पर आरोप है कि स्वीडन प्रत्यर्पित होने से बचने के लिए उन्होंने जमानत की शर्तें तोड़ीं और दूतावास में शरण ली। इक्वेडोर ने इस महीने कहा कि उसने ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए असांजे को अपनी नागरिकता दे दी है। असांजे को डर है कि लीक हुए गोपनीय अमरीकी दस्तावेजों को विकीलीक्स की ओर से प्रकाशित करने के मामले में अमरीका गुप्त तरीके से उन पर कार्रवाई कर सकता है और अमेरिकी अधिकारी उनके प्रत्यर्पण की मांग कर सकते हैं।